

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 24 फरवरी, 2015

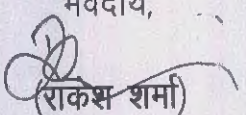
विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट उपयोग तथा प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों में ई-पेमेंट की प्रणाली लागू रहने के फलस्वरूप आहरण वितरण के कार्य हेतु आवश्यक निर्देश।

महोदय,

वित्तीय वर्ष के अधीन बजट एवं लेखा सम्बन्धी प्रक्रिया तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 125/XXVII(1)/2012, दिनांक 12 मार्च, 2012 का तथा शासनादेश संख्या 385/XXVII(1)/2014, दिनांक 19 मार्च, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित देयकों कोषागार/उपकोषागार में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त शासनादेशों में वर्णित प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

1. आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के अप्रैल माह में कैश की ऋणात्मक स्थिति से बचने तथा एक वित्तीय वर्ष का कैश भार ठीक बाद के वित्तीय वर्ष में अग्रणीत न हों इसके लिए सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी उन्हें अब तक आवंटित बजट के सापेक्ष समस्त देयको को प्रत्येक दशा में दिनांक 15 मार्च, 2015 तक कोषागारों/उप कोषागारों से पारित करना सुनिश्चित कर लें।
2. सभी प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को 20 मार्च, 2014 तक आवश्यक रूप से निर्गत कर दिया जाए तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष आवंटन कार्यस्थल (आहरण वितरण अधिकारी) तक विलम्बतम् रूप से 23 मार्च, 2015 तक आवश्य पहुच जाए।

3. सभी आहरण वित्तरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त देयकों को कम्प्यूटर से जनरेट कर विलम्बतम् रूप से 27 मार्च, 2015 में आवश्यक प्रस्तुत कर दिये जायें जिससे प्रस्तुत देयकों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा देयकों का आन लाइन पारित तथा ई-पेमेंट के माध्यम से 31 मार्च, 2015 तक भुगतान हेतु अथराईजेशन किया जा सके क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पारित देयकों का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा 31 मार्च, 2015 की रात्रि 8.00 बजे तक ही हो पाएगा।
 4. चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य में शासनादेश संख्या 454/XXVII(6)बी. 588-2014/2011, दिनांक 2 मई, 2014 द्वारा ई-सी0सी0एल0/ई-डी0सी0एल0 की प्रक्रिया तथा शासनादेश संख्या 117/XXVII(6)-बी.588-2014/2011, दिनांक 2 मई, 2014 द्वारा ई-पी0एल0ए0 की प्रक्रिया लागू है, अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दु-2 एवं 3 की व्यवस्था सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 एवं पी0एल0ए0 के ई-चेकों के भुगतानों में समान रूप से लागू होगी।
 5. कोषागारों/उपकोषागारों में ई-पेमेंट के लिए आहरण वितरण अधिकारियों से उक्तानुसार प्राप्त देयकों की चेकिंग विलम्बतम् रूप से 28 मार्च, 2015 तक आवश्यक रूप से किया जाय तथा ई-पेमेंट के लिए ट्रान्जेक्शन फाइल को विलम्बतम् रूप से दिनांक 29 मार्च, 2015 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय ताकि दिनांक 31 मार्च, 2015 के पूर्व ही ई-ट्रान्जेक्शन की जाँच कर ई-देयकों के भुगतान सफल अथवा असफल रहने की सही स्थिति ज्ञात हो सके।
 6. राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुये पार्किंग फण्ड हेतु धनराशि का न तो आहरण किया जाय तथा न कार्य होने की प्रत्याशा में ड्राफ्ट बनाकर रखा जाय। इस प्रकार का कृत्य वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी प्रशासकीय विभाग अपनी वित्तीय स्वीकृति की समय सारिणी इस प्रकार बना लें कि सभी स्वीकृतियों के देयकों हेतु कोषागार से प्राप्त चेकों का भुगतान दिनांक 31.03.2015 तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

 (राकेश शर्मा)
 अपर मुख्य सचिव

संख्या - 196 / XXVII(1) / 2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय को समस्त अनुभाग।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल० एन० पन्त)

अपर सचिव, वित्त